भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2816

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्थिक वृद्धि

2816. श्री इटेला राजेंदरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सात रणनीतिक और फ्रन्टियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाकर और विरासती औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और उसे बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति, स्वीकृत और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): केंद्रीय बजट 2026-27 में, सरकार ने सात रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने और उसे बनाए रखने की रणनीति की घोषणा की है। इस दिशा की पहलें निम्नानुसार हैं:

i. बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में उन्नति हेतु रणनीति) के तहत अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा ताकि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए ईकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके।

ii. उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 की शुरुआत करना; अप्रैल, 2025 में 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम के तहत परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करना; और खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने के

लिए समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर स्थापित करने के उद्देश्य से ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों को सहायता प्रदान करना।

iii. घरेलू रासायनिक उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्लस्टर-आधारित प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर चैलेंज रूट के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने में राज्यों का सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत करना।

iv. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की क्षमता निर्माण की दिशा में निम्नलिखित प्रस्तावित हैं: (क) सीपीएसई द्वारा 2 स्थलों पर डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सेवा ब्यूरो के रूप में हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय स्तर पर हाई प्रीसिशन वाले घटकों का व्यापक पैमाने पर और कम लागत पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे; (ख) निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) संवर्धन संबंधी एक स्कीम शुरू की जाएगी ताकि उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत सीआईई के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ किया जा सकें, जिसमें बहुमंजिला अपार्टमेंटों की लिफ्ट, बड़े और छोटे अग्निशमन उपकरण, मेट्रो और अधिक ऊंचाई वाले सड़कों के निर्माण के लिए सुरंग खोदने वाले उपकरण शामिल हैं; और (ग) एक कंटेनर विनिर्माण स्कीम की शुरुआत की जाएगी ताकि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण ईकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके, जिसके लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है।

v. श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए, निम्नलिखित 5 उप-भागों वाला एक एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है: (क) रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशा, मानव निर्मित रेशा और आधुनिक युग के रेशों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय रेशा स्कीम; (ख) मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के माध्यम से पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार स्कीम; (ग) मौजूदा स्कीमों को एकीकृत और सुदृढ़ करने तथा बुनकरों और कारीगरों को लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम; (घ) विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों तथा परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल; और (ङ) उद्योगजगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल विकास प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने के लिए समर्थ 2.0। इसके अतिरिक्त, तकनीकी वस्त्रों

में मूल्यसंवर्धन पर फोकस करने के लिए चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है।

vi. खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत करना। इससे वैश्विक बाजार लिंकेज, ब्रांडिंग और प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रक्रिया और उत्पादन की गुणवत्ता को सुव्यवस्थित करने और सहायता प्रदान करने देने में मदद मिलेगी।

vii. खेल-कूद की सामग्रियों के लिए एक समर्पित पहल, जो उपकरण डिजाइन के साथ-साथ सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवप्रयोग को बढ़ावा देगी।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2026-27 में, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार हेतु एक स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।

(ख): उपर्युक्त पहलों की घोषणा, हाल ही के केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है, और स्वीकृत तथा व्यय की गई निधियों के संबंध में कोई राज्य-वार विवरण उपलब्ध नहीं है।

****